श्लमबर्गर एशिया सर्विसेज लिमिटेड

बनाम

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मध्यस्थता याचिका संख्या 6/2013

09 मई, 2013

[सुरिंदर सिंह निजार,जे]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -एस. 11 (6)-याचिका अधीन-की ओर से नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी और तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति (पीठासीन) मध्यस्थ) मध्यस्थ न्यायाधिकरण में दोनों के बीच विवादों का निर्णय लेने के लिए पक्षकार-रखरखाव-क्या मध्यस्थता याचिका को सीमा के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि यह उठाती है मृत दावे या मामले को तय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण-आयोजितः मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश यह भी तय कर सकते हैं कि क्या दावा किया गया था एक मृत या एक लंबे समय से वर्जित दावा-लेकिन मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के लिए इन प्रश्नों पर निर्णय लेना अनिवार्य नहीं है। सीमा-इसे मध्यस्थ द्वारा तय करने के लिए छोड़ा जा सकता है न्यायाधिकरण-वर्तमान मामले में इस बात पर विवाद है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं को बार-बार नोटिस भेजे गए हैं। कभी भी प्राप्त किए गए थे-

आगे भी विवाद हैं (भले ही प्रतिवादी-ओ. एन. जी. सी.) द्वारा नोटिस प्राप्त किए गए थे कि क्या वे वास्तव में के सही खंड में प्राप्त किए गए थे प्रतिवादी-ओ. एन. जी. सी.-ये साक्ष्य के मामले हैं जो हैं - आम तौर पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना सबसे अच्छा है-यह उचित होगा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन धारा १६ का प्रयोग करते हुये किया जाये।

यह याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करने के लिए नामित मध्यस्थ की नियुक्ति और मध्यस्थ में तीसरे मध्यस्थ (पीठासीन मध्यस्थ) की नियुक्ति के लिए इस न्यायालय से निर्देश मांगा गया है।

प्रतिवादी ने अपने जवाबी हलफनामे में याचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने केवल अनावश्यक मुकदमेबाजी लाने के लिए वर्तमान मामला दायर किया है। मध्यस्थता याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और किए गए दावों पर लंबी अवधि की रोक लग जाती है और इसलिए ये मृत दावे हैं।

इसके विपरीत, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि सीमा नोटिस में उल्लिखित तिथि से चलना बंद कर देती है मध्यस्थता का आह्वान करते

हुए और वर्तमान मामले में मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस 14 नवंबर, 2008 को भेजा गया था कि किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्ता ने 9 जनवरी, 2012 को अंतिम नोटिस भेजा था और प्रतिवादी ने इनकार कर दिया था 29 फरवरी, 2012 के अपने पत्र के माध्यम से दावा, इस प्रकार, विवाद स्पष्ट रूप से 29 फरवरी, 2012 से ही उत्पन्न हुए थे और इसलिए, प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किया जाना चाहिए।

जिस प्रश्न पर विचार किया जाना था वह था क्या मध्यस्थता याचिका परिसीमा के आधार पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि यह मृत दावे उठाती है और यह इस न्यायालय के लिए मामले को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना।

न्यायालय ने मध्यस्थता याचिका को अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया

अभिनिर्धारितः 1. एस. बी. पी. एंड कंपनी मामले में फैसले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का घ्यान पूर्वक अवलोकन यह स्पष्ट है कि मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश यह भी तय कर सकते कि दावा मृत था या वर्जित दावा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे प्रश्नों पर सीमा पर निर्णय लें। इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ा जा सकता है। एस. बी. पी. एंड कंपनी मामले में की गई टिप्पणियों को श्लमबर्गर एशिया

सर्विसेज लिमिटेड द्वारा समझाया गया था। वी. तेल और प्राकृतिक 559 गैस निगम। लिमिटेड। इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड मामले में यह न्यायालय। इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के लिए यह तय करना वैकल्पिक है कि दावा समाप्त हो गया है या नहीं। प्रतिबंधित)। इस न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति ऐसा केवल तभी करेगा जब दावा स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से एक लंबे समय से वर्जित दावा हो। दावा को स्पष्ट रूप से लंबा समय-वर्जित कहा जा सकता है, अगर ठेकेदार इसे पूरा होने के एक दशक या उससे अधिक समय बाद करता है एक की किसी भी स्वीकृति का उल्लेख किए बिना काम करें दायित्व या अन्य कारक जो दावे को कानून में जीवित रखते हैं। दूसरी ओर, यदि ठेकेदार दावा करता है, जो पूरा होने के तीन साल की अवधि से थोड़ा अधिक है काम पूरा होने के पाँच साल के भीतर कहते हैं, अदालत तथ्य के विवादित प्रश्नों में प्रवेश नहीं करेंगे कि क्या दावा सीमा द्वारा वर्जित था या नहीं। फैसला आगे यह स्पष्ट करता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है साक्ष्य पर विस्तृत विचार। [पारस 16] [569-जी-एच; 570 -ए; 571-बी-डी]

एस. बी. पी. एंड कंपनी. बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्न। (2005) 8 एससीसी 618: 2005 (4) पूरक। एससीऔर 688; और

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बनाम एसपीएस इंजीनियरिंग लिमिटेड (2011) 3 एससीसी 507: 2011 (2) एस. सी. और. 512-पर निर्भर।

2. वर्तमान मामले में, एक विवाद है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार भेजे गए नोटिस उत्तरदाताओं को कभी प्राप्त किया गया था। आगे भी हैं विवाद (भले ही नोटिस ओ. एन. जी. सी. द्वारा प्राप्त किए गए हों) क्या वे वास्तव में ओ. एन. जी. सी. के सही खंड में प्राप्त किए गए थे। ये सबूत के मामले हैं जो आम तौर पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा छोड़ दिया जाता है। [पैरा 17] [571-ई-एफ]

3. इस न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करे।

मामला कानून संदर्भः

2005 (4) पूरक। एससीऔर 688 पैरा 12,15,16

2011 (2) एससीऔर 512 पैरा 15,16

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः मध्यस्थता याचिका सं 6/2013

याचिकाकर्ता के लिए संजीव पुरी, आदित्य छिब्बर, बी. के. सतीजा।

प्रतिवादी के लिए सिद्धार्थ लूथरा, एएसजी, गौरव अग्रवाल, शंकर नारायणन, अर्जुन दीवान।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

सुरिंदर सिंह निजार, जे. 1. यह याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 की धारा 11(6) के तहत दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी की ओर से नामित मध्यस्थ की नियुक्ति और मध्यस्थ में तीसरे मध्यस्थ (पीठासीन मध्यस्थ) की नियुक्ति के लिए इस न्यायालय से निर्देश मांगा गया है। पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करने के लिए न्यायाधिकरण।

2. याचिकाकर्ता हांगकांग के कानून के तहत निगमित और पंजीकृत कंपनी है जिसका परियोजना कार्यालय भारत में है और इसका एक आधार कार्यालय मुंबई में है। प्रतिवादी कंपनी अधिनियम , 1956 के तहत पंजीकृत एक निगम है जिसका पंजीकृत कार्यालय जीवन भारती टॉवर-2, 124, सर्कस नई दिल्ली में है।

3. प्रतिवादी ने अपने जवाबी हलफनामे में याचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने केवल अनावश्यक मुकदमेबाजी लाने के लिए वर्तमान मामला दायर किया है। मध्यस्थता याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और किए गए दावों पर लंबी अवधि की रोक लग जाती है और इसलिए ये मृत दावे हैं।

4. प्रारंभिक आपत्ति का निर्णय करने के लिए कुछ प्रासंगिक घटनाओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

5. याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने 7 दिसंबर, 2004 को एक अनुबंध किया और निष्पादित किया (6 अगस्त, 2004 के फर्म आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी)। खंड 27 के तहत अनुबंध याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के समाधान के लिए तंत्र के रूप में मध्यस्थता का प्रावधान करता है। मध्यस्थता खंड इस प्रकार है:

"27 मध्यस्थता

27.1 अनुबंध में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, यदि पार्टियों या उनके संबंधित प्रतिनिधियों या समनुदेशितियों के बीच, काम पूरा होने या छोड़ने से पहले या बाद में किसी भी समय कोई विवाद, मतभेद, प्रश्न या असहमति उत्पन्न होती है। निर्माण, अर्थ, संचालन, प्रभाव, व्याख्या या अनुबंध से बाहर या उसके उल्लंघन के संबंध में तीन मध्यस्थों से मिलकर एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाएगा। प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।

विवाद के निपटारे की इच्छा रखने वाली पार्टी को मध्यस्थता के लिए जाने के अपने इरादे की सूचना देनी होगी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा

जाएगा कि सभी विवादों का निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाएगा और अपना मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा और दूसरे पक्ष से 30 दिनों के भीतर अपना स्वयं का मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहा जाएगा। यदि कोई पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है या नियुक्त किए गए दो मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत होने में विफल रहते हैं, किसी पक्ष के अनुरोध पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति या संस्था (अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में) मध्यस्थों/पीठासीन मध्यस्थों की नियुक्ति करेगा। घरेलू अनुबंधों के मामले में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति या संस्था जिसके अधिकार क्षेत्र में विषय खरीद आदेश/अनुबंध रखा/बनाया गया है, किसी एक पक्ष के अनुरोध पर मध्यस्थ/पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। .

यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे दिया जाता है, अक्षम हो जाता है या किसी भी कारण से कार्यवाही से हट जाता है, तो संबंधित पक्ष/मध्यस्थों के लिए उपरोक्त तरीके से उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना वैध होगा। ऐसा व्यक्ति उस चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ेगा जहां उसके पूर्ववर्ती ने छोड़ा

था यदि दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हों; अन्यथा, वह नए सिरे से आगे बढ़ेगा।

यह अनुबंध की एक शर्त है कि मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष मध्यस्थता के आह्वान के समय सभी विवादों को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करेगा, उसके बाद नहीं।

यह अनुबंध की एक शर्त भी है कि अनुबंध का कोई भी पक्ष पुरस्कार की राशि पर किसी भी एंटी-लाइट (पूर्व-संदर्भ) या पेंडेंट-लाइट ब्याज का हकदार नहीं होगा।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण तर्कसंगत निर्णय देगा और वही अंतिम, निर्णायक और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

मध्यस्थता का स्थान मुंबई, भारत में होगा।

यह अनुबंध की शर्त है कि मध्यस्थता की लागत पार्टियों द्वारा समान शेयरों में वहन की जाएगी।

उपरोक्त के अधीन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान और उसके बदले में कोई भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा।

अनुबंध के खंड 26 में आगे निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

"26 क्षेत्राधिकार और लागू कानून:

इस समझौते से जुड़े सभी मामलों सहित यह समझौता, फिलहाल लागू भारत के कानूनों (मौलिक और प्रक्रियात्मक दोनों) द्वारा शासित होगा और मुंबई में भारतीय न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। भारत में काम करने वाली या भारत में संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने वाली विदेशी कंपनियों को देश के कानून का पालन करना होगा और किसी भी तरह से भारतीय कानूनी प्रणाली की अनदेखी के लिए कोई समझौता या बहाना नहीं होगा।

6. याचिकाकर्ता अपने सहयोगियों के साथ एक अग्रणी तेल क्षेत्र सेवा प्रदाता है। इस पर भारत सहित दुनिया भर की तेल और गैस कंपनियों के लिए बेहतर परिणाम और बेहतर E&P प्रदर्शन देने का भरोसा है। अपने अच्छे साइट संचालन, अनुसंधान और इंजीनियरिंग सुविधाओं के माध्यम से, यह ऐसे उत्पादों, सेवाओं और समाधानों को विकसित करने के लिए काम कर रहा है जो ग्राहकों के प्रदर्शन को सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल तरीके से अनुकूलित करते हैं। इसमें भारत सहित 85 देशों में काम करने वाले 140 से अधिक राष्ट्रीयताओं के 113,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं।

7. प्रतिवादी अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ड्रिलिंग के दौरान माप के चार सेट (एमडब्ल्यूडी) और जाइरो उपकरण और सेवाओं (जाइरो) के एक सेट को किराए पर लेने का इच्छुक था, जिसे सामूहिक

रूप से "उपकरण" कहा जाता है। तदनुसार, प्रतिवादी ने एक निविदा संख्या MR/DS/MAT/CT/MWD/ 142(390) 2003- 04/P46KC04002 जारी की। जैसा कि निविदा में कहा गया है, याचिकाकर्ता के पास संचालन करने का आवश्यक अनुभव था और उसने प्रतिवादी की निविदा के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव संख्या एसएएसएल/डीएंडएम/ओएनजीसी 4002/2002-02 के तहत 8 जून, 2004 को बोली प्रस्तुत की थी। उसमें निर्धारित नियम और शर्तें। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की बोली स्वीकार कर ली और 6 अगस्त, 2004 को क्रमांक MR/DS/MAT/CT/MWD/142(390)2003-04/DY8DF0301/ 9010002261 के तहत एक ठोस आदेश दिया। तदनुसार, 7 दिसंबर, 2004 को, पार्टियों ने फर्म ऑर्डर जारी होने की तारीख यानी 6 अगस्त, 2004 से प्रभावी एक अनुबंध में प्रवेश किया और विधिवत निष्पादित किया। याचिकाकर्ता अनुबंध के परिशिष्ट-III में परिभाषित कार्य करने के लिए सहमत हुआ। इस पर विचार करते हुए प्रतिवादी ने अनुबंध के परिशिष्ट-IV में निर्धारित समय पर और अनुबंध में निर्धारित तरीके से राशि का भुगतान करने का वादा किया। अनुबंध की अवधि प्रारंभ में न्हावा बेस पर "उपकरण" की प्राप्ति की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए थी। प्रतिवादी के पास समान दर, नियम और शर्तों पर छह-छह महीने की दो समान किस्तों में अनुबंध को एक वर्ष और बढ़ाने का विकल्प था। समान दरों, नियमों और शर्तों पर चालू कुओं में काम पूरा करने के लिए अनुबंध

स्वचालित रूप से विस्तार योग्य था। याचिकाकर्ता का दावा है कि चूंकि वह प्रतिवादी को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा था, इसलिए अनुबंध को छह महीने की पहली किस्त के लिए 16 अक्टूबर, 2006 से 15 अप्रैल, 2007 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद, इसे अनुबंध के विशेष नियमों और शर्तों के खंड 2.0 में निहित समान दरों, नियमों और शर्तों पर छह महीने की दूसरी किस्त के लिए 16 अप्रैल, 2007 से 15 अक्टूबर, 2007 तक बढ़ा दिया गया था।

8. याचिकाकर्ता का आगे दावा है कि उसने अनुबंध के अनुसार काम किया और समय-समय पर किए गए काम के लिए चालान जारी किए। हालाँकि, 481,252.65 अमेरिकी डॉलर और 9,565,616 रुपये की राशि के चालान या तो कम भुगतान किए गए थे या याचिकाकर्ता द्वारा अनुबंध के तहत काम संतोषजनक ढंग से किए जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए चालान का विवरण इस प्रकार है:

चालान संख्या	अवधि	राशि (यूएसडी)
800001820	मार्च 2006	128,630.00
800001821	मार्च 2006	89,149.00
800001828 बी	मार्च 2006	31,053.00
800001829 बी	मार्च 2006	41,406.00
800002119	सितम्बर 2006	192,169.00

800002120 बी	सितंबर 2006	63,729.00
800002860	सितंबर 2007	71,304.00
800002861 बी	सितंबर 2007	96.00
800002862 बी	सितंबर 2007	49,487.00
	कुल	667,023.00

9. याचिकाकर्ता का आगे दावा है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त चालान के खिलाफ भुगतान करने से इनकार कर दिया है। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के विभिन्न लॉस्ट इन होल (एलआईएच) दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, यदि साइट पर "उपकरण" खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो प्रतिवादी 50 की सीमा के अधीन छेद में फंसे/खोए हुए "उपकरण" के मूल्यह्रास प्रतिस्थापन मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। % की गणना भारत में ऐसे "उपकरणों" के प्रथम उपयोग की तारीख से की जाती है। इसके अलावा, अनुबंध के खंड 17 के संदर्भ में, प्रतिवादी उक्त उपकरणों को पुनर्प्राप्त करने या पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए बाध्य था, लेकिन प्रतिवादी इस दायित्व का भी निर्वहन करने में विफल रहा।

10. चूंकि कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था, याचिकाकर्ता ने 11 जुलाई, 2008 को प्रतिवादी को एक पत्र भेजकर बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की। हालाँकि, उपरोक्त संचार का कोई जवाब नहीं आया।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने अनुबंध के खंड 27 के तहत मध्यस्थता का आह्वान करते हुए 14 नवंबर, 2008 को एक कानूनी नोटिस जारी किया। उपरोक्त नोटिस में, याचिकाकर्ता ने पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों का विवरण दिया। उसी नोटिस में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को सूचित किया कि उसने मध्यस्थ को नामित किया है और प्रतिवादी से नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने मध्यस्थ को नामित करने के लिए कहा है, ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए कानूनी कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। प्रतिवादी की ओर से मध्यस्थ की। याचिकाकर्ता के अनुसार, उपरोक्त नोटिस प्रतिवादी को विधिवत दिया गया था लेकिन मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने 21 मई, 2009 को एक अनुस्मारक पत्र भेजा जिसमें प्रतिवादी से नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक मध्यस्थ को नामित करने का आह्वान किया गया। याचिकाकर्ता ने दोहराया कि यदि प्रतिवादी अभी भी मध्यस्थ को नामित करने में विफल रहता है, तो याचिकाकर्ता प्रतिवादी की ओर से मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कार्यवाही शुरू करेगा। याचिकाकर्ता द्वारा 11 अगस्त, 2010 को पहले के नोटिस और अनुस्मारक के समान ही एक और अनुस्मारक जारी किया गया था। फिर भी प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण याचिकाकर्ता को 9 जनवरी, 2012 को एक और नोटिस भेजना पड़ा। अंततः, 29 फरवरी, 2012 को, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को एक जवाब

भेजा, जिसमें इस बात से इनकार किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई कोई भी राशि देय थी।

11. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता ने अंततः स्वीकार कर लिया कि पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है और मध्यस्थता और सुलह *अधिनियम 1996 की धारा 11(6)* के तहत वर्तमान याचिका दायर की है और प्रतिवादी की ओर से नामित मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की है। तीसरा मध्यस्थ (पीठासीन मध्यस्थ)।

12. मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने प्रस्तुत किया है कि: (1) याचिकाकर्ता ने 2007 में बिना किसी देरी के भुगतान स्वीकार कर लिया था। इसलिए, दावे पहले ही तय हो चुके हैं; (2) याचिकाकर्ता द्वारा 2007 में भुगतान स्वीकार करने पर अनुबंध बहुत समय पहले समाप्त हो गया था; (3) कार्रवाई का कारण, यदि कोई हो, 2007 में उत्पन्न हुआ, जबकि मध्यस्थता याचिका जनवरी, 2013 में दायर की गई है; (4) श्री लूथरा के अनुसार, याचिकाकर्ता की दलीलों पर भी, 14 दिसंबर, 2008 से यानी 30 दिनों की समाप्ति पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11(6) के तहत याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता के पास कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। 14 नवंबर, 2008 के पहले नोटिस से मध्यस्थता का आह्वान किया गया। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिका उक्त तिथि से अधिकतम 3 वर्ष की

अवधि के भीतर, यानी 14 दिसंबर, 2011 को या उससे पहले दायर की जानी चाहिए थी, जबकि वर्तमान याचिका 11 जनवरी, 2013 को दायर की गई है। विद्वान वरिष्ठ वकील इस बात पर जोर दिया गया कि यह न्यायालय वर्तमान याचिका पर विचार नहीं करेगा क्योंकि यह बेकार दावों को उठाता है। 21 अक्टूबर, 2007 को अंतिम इकाई की डी-हायरिंग के बाद अनुबंध समाप्त हो गया। प्रतिवादी को पूरी राशि वर्ष 2006-07 में प्राप्त हुई थी। जवाबी हलफनामे में दिए गए कथनों की ओर इशारा करते हुए, श्री लूथरा का कहना है कि 14 नवंबर, 2008, 21 मई, 2009 और 11 अगस्त, 2010 के पत्र, जो ओएनजीसी को लिखे गए थे, ओएनजीसी के संबंधित अनुभाग में प्राप्त नहीं हुए थे।. पत्राचार के लिए अनुबंध में पता ओएनजीसी लिमिटेड, ड्रिलिंग सर्विसेज, मुंबई क्षेत्र, 3 बी, वसुंधरा भवन, बांद्रा-पूर्व, मुंबई-51 दिया गया था। इसे अक्टूबर, 2005 में ओएनजीसी लिमिटेड, ड्रिलिंग सर्विसेज, डायरेक्शनल ड्रिलिंग सेक्शन, मुंबई क्षेत्र, दूसरी मंजिल, 11-हाई, ओएनजीसी, सायन (डब्ल्यू), मुंबई -400017 में बदल दिया गया था। यह याचिकाकर्ता को ज्ञात था क्योंकि उसने प्रस्तुत किया था नए पते पर ओएनजीसी को चालान। हालाँकि, 21 मई, 2009 और 11 अगस्त, 2010 के नोटिस अभी भी पहले के पते पर भेजे गए थे। किसी भी स्थिति में, 14 नवंबर, 2008 का नोटिस प्रतिवादी को कभी प्राप्त नहीं हुआ। श्री लूथरा का कहना है कि केवल बाद में कारण बताओ नोटिस/पत्र भेजने से सीमा का विस्तार नहीं होगा क्योंकि कार्रवाई के कारण की तारीख 14 नवंबर, 2008

के पहले नोटिस से 30 दिनों की समाप्ति पर तय की गई थी। श्री लूथरा बताते हैं कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की 1996 धारा 43 में प्रावधान है कि सीमा अधिनियम 1963 मध्यस्थता पर उसी तरह लागू होगा जैसे यह अदालत में कार्यवाही पर लागू होता है। धारा 21 के साथ पठित धारा 43(2) पर भरोसा करते हुए उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता उस तारीख से शुरू हुई मानी जाएगी जिस दिन मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवाद का अनुरोध प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया जाता है। याचिकाकर्ता ने 14 नवंबर, 2008 को पहला नोटिस भेजा था, मध्यस्थता याचिका उसके 30 दिन की समाप्ति के बाद दायर की जानी चाहिए थी। विद्वान वकील एसबीपी एंड कंपनी बनाम में इस न्यायालय की संविधान पीठ पर भरोसा करते हैं। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड एवं अन्य। (2005) 8 एससीसी 618, इस दलील के समर्थन में कि वर्तमान याचिका परिसीमा द्वारा वर्जित है। वह फैसले के पैरा 39 पर भरोसा करते हैं, जो इस प्रकार है:

"39. यह परिभाषित करना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन के साथ संपर्क करने वाले मुख्य न्यायाधीश को उस चरण में वास्तव में क्या निर्णय लेना है। जाहिर है, उसे इस अर्थ में अपना अधिकार क्षेत्र तय करना होगा कि क्या प्रस्ताव देने वाली पार्टी ने सही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उसे यह तय करना होगा कि क्या कोई मध्यस्थता समझौता है, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है

और क्या जिस व्यक्ति ने उसके समक्ष अनुरोध किया है, वह ऐसे समझौते में एक पक्ष है। यह इंगित करना आवश्यक है कि वह इस प्रश्न का निर्णय भी कर सकता है कि क्या दावा मृत था; या लंबे समय से अटका हुआ दावा जिसे पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी और क्या पार्टियों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके लेनदेन पूरा किया है। उस स्तर पर यह तय करना संभव नहीं हो सकता है कि किया गया दावा मध्यस्थता खंड के दायरे में आता है या नहीं। उस प्रश्न को मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य लेने के साथ-साथ मध्यस्थता में शामिल दावों के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए छोड़ देना उचित होगा। मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना होगा कि आवेदक ने अधिनियम की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शर्तों को पूरा किया है या नहीं। इन पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए मुख्य न्यायाधीश या तो हलफनामों और पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं या ऐसे साक्ष्य ले सकते हैं या ऐसे साक्ष्य दर्ज करवा सकते हैं, जो आवश्यक हो। हमारा मानना है कि अधिनियम के संदर्भ में इस प्रक्रिया को अपनाने से मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के विभिन्न चरणों में अदालत के बहुत अधिक दृष्टिकोण के बिना, मध्यस्थता की प्रक्रिया में तेजी लाने के अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की पूर्ति सबसे अच्छी होगी।

13. उपरोक्त टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय को यह तय करना होगा कि क्या याचिका परिसीमा के आधार पर खारिज की जा सकती है क्योंकि यह मृत दावे उठाती है। इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ दे।

14. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री संजीव पुरी का कहना है कि मध्यस्थता लागू करने वाले नोटिस में उल्लिखित तारीख से सीमा समाप्त हो जाती है और वर्तमान मामले में, मध्यस्थता लागू करने वाला नोटिस 14 नवंबर को भेजा गया था। 2008. विद्वान वकील ने इस दलील के समर्थन में मध्यस्थता और_सुलह अधिनियम की 1996 धारा 3 पर भी भरोसा किया कि नोटिस को प्रतिवादी द्वारा प्राप्त हुआ माना जाता है क्योंकि यह अनुबंध में उल्लिखित पते पर वितरित किया गया था।_किसी भी स्थिति में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने 9 जनवरी, 2012 को अंतिम नोटिस भेजा था और प्रतिवादी ने 29 फरवरी, 2012 के अपने पत्र के माध्यम से दावे से इनकार कर दिया था। विवाद स्पष्ट रूप से 29 फरवरी, 2012 से ही उत्पन्न हुए थे। इसलिए, प्रतिवादी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति खारिज किए जाने योग्य है।

15. किसी भी घटना में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम के मामले में है। एसपीएस इंजीनियरिंग लिमिटेड (2011) 3 एससीसी 507 ने एसबीपी एंड कंपनी के मामले (सुप्रा) में संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया और समझाया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि परिसीमा के प्रश्न पर, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि यह मामला ट्रिब्यूनल के निर्णय पर छोड़ दिया जाएगा कि क्या किया गया दावा परिसीमा द्वारा वर्जित है या नहीं।

16. मैंने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है। एसबीपी एंड कंपनी (सुप्रा) में फैसले के पैराग्राफ 39 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का एक मात्र अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश यह भी तय कर सकते हैं कि दावा मृत था या लंबे समय से वर्जित दावा था. लेकिन मुख्य न्यायाधीश या उनके पद पर नियुक्त न्यायाधीश के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे शुरुआती स्तर पर ही प्रश्नों पर निर्णय लें। इसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय करने के लिए छोड़ा जा सकता है। एसबीपी एंड कंपनी (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों को इस न्यायालय द्वारा इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में समझाया गया था, जो इस प्रकार हैं:

"14. यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई दावा न्यायिक निर्णय द्वारा वर्जित है, या क्या कोई दावा "दुर्भावनापूर्ण" है, तथ्यों और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच करना आवश्यक होगा। अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन में यह तय किया जाना है कि क्या पार्टियों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता है। अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी आवेदन में मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति से दावे के गुण-दोष पर जाने या दावे की वैधता की जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति यह तय करने का विकल्प चुन सकते हैं कि क्या दावा एक मृत (लंबे समय से वर्जित) दावा है या क्या पार्टियों ने संतुष्टि दर्ज करके, अनुबंध के तहत सभी अधिकारों, दायित्वों और उपचारों को समाप्त कर दिया है, ताकि न तो अनुबंध और न ही अनुबंध समाप्त हो सके। मध्यस्थता समझौता बच गया. जब यह कहा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश या उनके पदनाम यह तय कर सकते हैं कि दावा एक मृत दावा है या नहीं, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह ऐसा केवल तभी करेंगे जब दावा स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से लंबे समय से बाधित दावा हो और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है साक्ष्य के किसी भी विस्तृत विचार के लिए। हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं: यदि ठेकेदार किसी दायित्व की स्वीकृति या कानून में दावे को जीवित रखने वाले अन्य कारकों का उल्लेख किए बिना काम पूरा होने के एक दशक या उसके बाद दावा करता है, और दावा स्पष्ट रूप से लंबे समय से वर्जित है।

मुख्य न्यायाधीश या उनके पदनाम इस बात की जांच करेंगे कि क्या दावा एक मृत दावा है (अर्थात, एक लंबे समय से बाधित दावा)। दूसरी ओर, यदि ठेकेदार काम पूरा होने के तीन साल से अधिक, लेकिन काम पूरा होने के पांच साल के भीतर भुगतान का दावा करता है, और आरोप लगाता है कि अंतिम बिल तैयार किया गया था और भुगतान तीन साल के भीतर किया गया था। दावा, न्यायालय किसी विवादित प्रश्न पर विचार नहीं करेगा कि दावा परिसीमा द्वारा वर्जित था या नहीं। कोर्ट इस मामले को ट्रिब्यूनल के फैसले पर छोड़ देगा। यदि स्पष्ट और स्पष्ट मृत दावों और सीमा के विवादित मुद्दों से जुड़े दावों के बीच अंतर को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति अधिनियम की धारा 11 के तहत सभी आवेदनों में सीमा के प्रश्न का निर्णय करेंगे।

इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्य न्यायाधीश या उनके पदनाम के लिए यह तय करना वैकल्पिक है कि दावा समाप्त हो गया है (लंबे समय से वर्जित)। इस न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति ऐसा तभी करेंगे जब दावा स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से लंबे समय से बाधित दावा हो। दावे को स्पष्ट रूप से लंबे समय से बाधित कहा जा सकता है, यदि ठेकेदार किसी दायित्व की स्वीकृति या कानून में दावे को जीवित रखने वाले अन्य कारकों का उल्लेख किए बिना काम पूरा होने के एक दशक या उससे भी अधिक समय बाद दावा करता है। दूसरी ओर, यदि ठेकेदार कोई दावा

करता है, जो काम पूरा करने की तीन साल की अवधि से थोड़ा अधिक है, जैसे कि पूरा होने के पांच साल के भीतर, तो न्यायालय तथ्य के विवादित प्रश्नों पर विचार नहीं करेगा कि क्या दावा वर्जित था। सीमा है या नहीं. निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि साक्ष्य पर विस्तृत विचार की कोई आवश्यकता नहीं है।

17. वर्तमान मामले में, इस बात पर विवाद है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं को बार-बार भेजे गए नोटिस कभी प्राप्त हुए थे। इस बारे में और भी विवाद हैं (भले ही नोटिस ओएनजीसी द्वारा प्राप्त किए गए हों) कि क्या वे वास्तव में ओएनजीसी के सही अनुभाग में प्राप्त हुए थे। ये साक्ष्य के मामले हैं जिनका निर्णय आम तौर पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना बेहतर होता है।

18. मेरी राय में, इस न्यायालय के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 की धारा 11(6) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन करना उचित होगा। उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं न्यायमूर्ति वी.एन. को नामित करता हूं। खरे, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में और न्यायमूर्ति डीपी वाधवा और न्यायमूर्ति एसएन वरियावा, इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों का फैसला करने के लिए मध्यस्थ के रूप में हैं। मध्यस्थ पक्षों के परामर्श से अपना पारिश्रमिक स्वयं तय करेंगे।

19. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के साथ-साथ अन्य मध्यस्थों को भी सूचित करे, ताकि वे जल्द से जल्द संदर्भ में प्रवेश कर सकें।

20. इन टिप्पणियों के साथ, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के मध्यस्थता याचिका की अनुमति दी जाती है।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद और आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास कुमार स्वामी, और जे. एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उदेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।